ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-2*March- 2018
Innovation The Research Concept

उच्च शिक्षा प्रणाली के समक्ष समस्यायें एवं समाधान

अजीत कुमार यादव
शोधार्थी,
शिक्षा संकाय,
आर0बी0एस0 कालेज,
आगरा

सारांश

किसी भी देश का गौरव उसकी शिक्षा व्यवस्था एवं उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही मानव संसाधनों को बढ़ावा देती है और राष्ट्रीय उत्पादन में सहायक होती है। आजादी के उपरान्त हमने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास किया है परन्तु वर्तमान परिदृश्य में उच्च शिक्षा के स्तर को और ऊँचाईयों पर ले जाने की आवश्यकता है। क्योंकि यह युवा पीढ़ी का आधार भी है और भविष्य भी। उच्च शिक्षा का सफल समुन्नत विस्तार ही राष्ट्र के स्तरोन्नयन का मुख्य साधन है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान परिदृश्य में कई ऐसे विचारणीय महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर दृष्टिपात करना आवश्यक है और भविष्य के लिये जरूरी भी, उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों का समावेशन देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में विकास की नई गाथा लिखेगा।

मुख्य शब्द : भारतीय शिक्षा प्रणाली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

प्रस्तावना

शिक्षा मानव विकास की पूर्ण अभिव्यक्ति है। शिक्षा किसी भी देश के विकास की सबसे अहम कड़ी है। देश का विकास देश की शैक्षिक स्थिति पर निर्भर होता है। अतः शिक्षा का स्तर जितना उच्च और गुणवत्तायुक्त होगा उस देश की सामाजिक सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति भी उतनी ही सुदृढ़ होगी। कहते हैं जिस देश की शिक्षा व्यवस्था में जितना ही लचीलापन एवं तरलता होगी, उस राष्ट्र का निर्माण भी उतनी तेजी से होगा। भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति को देखना है तो सर्वप्रथम हमें प्राचीन एवं मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था को देखना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि यह युग वास्तव में उच्च शिक्षा के चरम युगों में सुमार है। प्राचीन शिक्षा में ही भारतीय धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, वेदों की रचना हुयी जो आज भी कहीं न कहीं भारतीय शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। भारतीय शिक्षा का दूसरा पड़ाव बौद्ध शिक्षा का आता है जिसने भारतीय शिक्षा प्रणाली का चहुमुखी विकास किया चाहे, उच्च शिक्षा हो या प्राथमिक शिक्षा अपने श्रेष्ठतम शिक्षण विधियों एवं अनेक विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के माध्यम से भारतीय शिक्षा को आगे ले जाने और भारत को विश्वगुरू बनाने का कार्य किया। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में भी उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी, परन्तु वैदिक और बौद्ध युगीन शिक्षा के विपरीत मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में एक विशेष अन्तर था, मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा प्राचीन शाश्वत मूल्यों (त्याग एवं सादगी) की भावना से इतर वैभवपूर्ण सुखसुविधाओं के उपयोग पर विश्वास रखती थी, बावजूद इसके मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था ने भी भारतीय शिक्षाप्रणाली को आगे बढ़ाया परन्तु भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से संचालित करने का श्रेय अंग्रेजों को है, शिक्षा में सुधार हेतु अनेक आयोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये और जिसे अमल करने और आगे बढ़ने का एक लम्बा इतिहास भारतीय शिक्षा प्रणाली का है जिसे हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी जारी रखा है। जिसमें 1948 में प्रख्यात शिक्षाविद डा0 राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। जिसने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संगठनात्मक, संरचनात्मक, प्रशासनिक एवं वृत्तीय सुधारों को बखुबी संचालन किया है। भारत एक युवा देश है जिसकी आबादी का बहुलांश युवा है। भारत में जहां 2020 में 4.70 करोड़ कामकाजी लोग अतिरिक्त होंगे, वहीं अकेले अमेरिका में 1.70 करोड़ लोगों की कमी होगी इन जनसांख्यकी प्रवृत्तियों का लाभ यदि भारत को उठाना है तो उसे अपने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता व उसकी उपलब्धता सुलभ कराने के प्रयास करने होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली हमारी 18–24 वर्ष की आबादी का अनुपात लगभग 7 प्रतिशत है, जो, एशिया की औसत का सिर्फ आधा है। विश्वविद्यालयों में उपलब्ध

स्थानों की संख्या दृष्टि से उच्च शिक्षा के लिए मौजूदा अवसर हमारी जरूरतों के लिये बिल्कुल ही पर्याप्त नही है। हमें उच्च शिक्षा में सफल भर्ती अनुपात 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि यदि हमें समान शिक्षा, सबके लिए शिक्षा जैसे आदर्शों को पाना है तो अगले 5 वर्षों में नामांकन अनुपात को दो गुना करना होगा और लगभग 1500 नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी होगी, जिनकी मदद से भारत 2020 तक कम से कम प्रतिशत का सकल भर्ती अनुपात हासिल कर सके।

उच्च शिक्षा में आवश्यकता

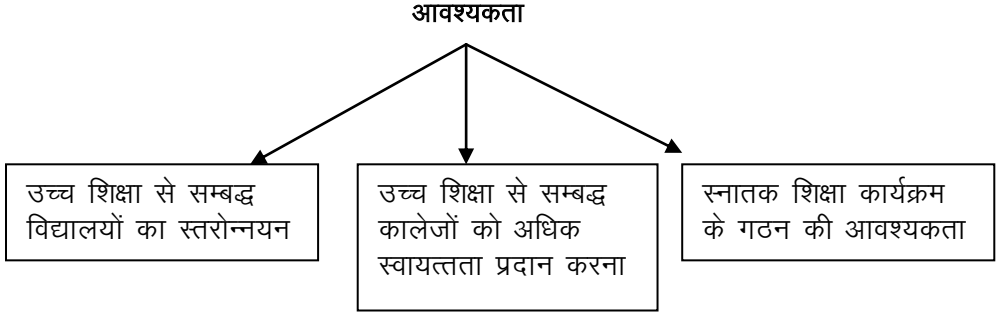

हमारी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं समसामयिक स्थिति में बदलाव एवं सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा सकती है। उच्च शिक्षा को रोजगारपरक बनाए जाने की जरूरत है। शिक्षा को ज्यादा उपयोगी और कौशल से युक्त साथ ही साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने वाली शिक्षा बनाने के लिए मुख्यतः तीन सूत्रीय कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

1. शिक्षण प्रणाली में उद्यमशीलता के महत्वपूर्ण प्रयास कालेज स्तर से ही करने होंगे जिससे छात्रों को उद्यमों की स्थापना के प्रति उन्मुख किया जा सके।
2. बैंकों को युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वह आत्मनिर्भर हो सके और नवीन उत्पादों का उत्पादन करके आय अर्जित कर सकें।
3. मानव संसाधन के क्षेत्र में अर्थगत दृढ़ता की आवश्यकता है। जिससे बाजार योग्य उत्पाद बन सके और लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो सके।
4. विश्वविद्यालय, एवं विद्यालयी स्तर पर सरकारी एवं निजी उद्यमों को और ज्यादा समावेशन की आवश्यकता है जिससे रोजगार शीलता की गति बनी रहे।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध में विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करना।

1. उच्च शिक्षा में आने वाली आवश्यकताओं का अध्ययन करना।
2. उच्च शिक्षा से सम्बन्धित प्रकमों में संस्थागत एवं प्रशासनिक सुधारों का अध्ययन करना।
3. उच्च शिक्षा में अन्य विचारणीय मुद्दों का अध्ययन करना।

पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता

उच्च शिक्षा को कभी–कभी माध्यम की समस्याओं से भी रूबरू होना पड़ता है। हमारे यहां आज हिन्दी या अंग्रेजी में शिक्षा जैसी समस्यायें व्याप्त है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे बहुत से छात्र माध्यम की समस्या से जूझ रहे हैं और बहुतेरों को तो यह भी नही पता कि वह यह शिक्षा क्यों प्राप्त कर रहे है। अतः हमारे यहाँ उद्देश्यहीनता की स्थिति है। जो कहीं न कहीं पाठ्यक्रमों के संकुचित और रोचक ना होने के कारण भी हो सकता है। गुणवत्ता युक्त विषयवस्तु का प्रबन्ध उच्च शिक्षा का अनिवार्य अवयव होना चाहिए। शिक्षा के तीन महत्वपूर्ण घटक, व्याख्यान, प्रैक्टिकल या प्रयोगशाला और पुस्तकालय को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए।

1. विश्वविद्यालयों में तीन वर्षों में कम से कम एक बार अपने पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना चाहिये, एवं संसाधनों की उचित समीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
2. विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा शोध अध्ययन के जरिये विषय का सर्वांगीकरण किया जाये, जिससे गुणवत्तावाली सर्जनात्मक विषयवस्तु तैयार की जा सके एवं इस संदर्भ में शिक्षकों की स्वायत्तता का ध्यान दिया जाये।
3. विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के स्वरूप का भी मूल्यांकन करना होगा, क्योंकि अक्सर सीखने एवं सीखाने की प्रक्रिया में कोई बेहतर माडल का प्रयोग न होना प्रक्रिया को बाधित कर देता है। अतः परिक्षाओं का स्वरूप समग्र विश्लेषण का होना चाहिए जिसमें विद्यार्थियों के रचनात्मक स्रोतों पर ध्यान दिया जाना चाहिये रटन्त विद्या को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये।
4. विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अधिक विविधता लचीलापन एवं सार्वभौमिकता लाने की आवश्यकता है। सम्पूर्ण देश में समान पाठ्यक्रमों को लागू करने की भी जरूरत है। क्रेडिट व्यवस्था भी एक उपयोगी व्यवस्था हो सकती है।

विश्वविद्यालयी प्रशासनिक ढांचे में सुधार की आवश्यकता

भारत में विश्वविद्यालय की स्थिति चिंताजनक है और इसमें सुधार तभी सम्भव है जब हम इसके प्रशासनिक ढांचों में सुधार करें।

1. शिक्षकों और छात्रों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी, जवाबदेही युक्त व लोकतांत्रिक हो,
2. गैर शैक्षिक दखलंदाजी विश्वविद्यालयों में न हो,
3. कुलपतियों की नियुक्ति में सरकारी एवं राजनीतिक हस्तक्षेप का आभाव हो,

4. युनिवर्सिटी कोर्ट्स विद्वत परिषदों व कार्यकारी परिषदों का उचित विनियमन हो,
5. शैक्षणिक सत्र का सख्ती से पालन हो, और सम्बद्ध महाविद्यालयों के वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबंधन पर सख्त नजर रखी जाये,

संसाधनों में वृद्धि एवं उचित उपयोग की आवश्यकता

विश्वविद्यालयों में संसाधनों के उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों द्वारा अनुमोदित धन का 75 प्रतिशत हिस्सा वेतन और पेंशन पर खर्च होता है। बाकी 25 प्रतिशत में कम से कम 15 प्रतिशत विकास, बिजली आदि पर चला जाता है और बाकी परीक्षाओं के आयोजन में। ऐसी स्थिति में नवीन शोधों एवं शैक्षणिक कार्यों पर धन कम ही होता है। वर्तमान समय शिक्षा के लिए जी0डी0पी0 का 3.6 प्रतिशत हिस्सा ही दिया गया है जो किसी भी तरह से पर्याप्त नही है और इसमें उच्च शिक्षा का प्रतिशत 1.5 प्रतिशत है जो और भी विचारणीय है। यदि भारतको अपनी पुरानी विश्वगुरू की छवी को पाना है तो हमें इस क्षेत्र में और मद बढ़ाने होंगे। फीस को युक्तिसंगत रूप से बढ़ाना होगा फीस से विश्वविद्यालयों के खर्च का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा पूरा होना चाहिए।

उच्च शिक्षा पर विचारणीय अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

10वीं और 12वीं कक्षा के पश्चात करीब 70 लाख लोग रोजगार तलाशने लगते है। परन्तु यहाँ रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था ऐसी नही है कि सभी के लिए रोजगार को जुटाया जा सके और ऐसी स्थिति में ही सामाजिक अस्थिरता पैदा होती है। वर्तमान आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए अपेक्षित कौशल और अधिकतम छात्रों तक इसकी पहुंच में बड़ा अन्तर है इसी अन्तर को पाटने के लिए हमें–

1. वित्तीय समावेशन
2. संपत्तियों का बेहतर प्रयोग
3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
4. Governmental Body एवं N.G.O.S. में सामन्जस्य
5. निजी निवेशकों को उच्च शिक्षा में अधिक मात्रा में आकर्षित करने के लिए विशेष छूट देनी होगी।

संख्या एवं आकार की दृष्टि से देखें तो भारत में लगभग 300 विश्वविद्यालय है जो उच्च शिक्षा की जरूरतों के संदर्भ में पर्याप्त नही है और भारत में युवाओं की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के उच्च शिक्षा में भर्ती अनुपात को बढ़ाना होगा, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को भी आगे लाना होगा जिसके लिये–

1. राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का निर्माण
2. स्पर्धा करने की क्षमता का विकास
3. कार्य उत्कृष्ठता हासिल करने की चेतना विकसित करनी होगी

वस्तुतः राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों को मान कर यदि रणनीति बनायी जाये तो सम्भवतः हमें बहुत हद तक सफलता प्राप्त होगी।

निवेश	परिवर्तन	समावेशी प्रकृति
1. नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना (2020 तक लगभग 1500)	वर्तमान विश्वविद्यालयों में सुधार	शिक्षा सभी के लिये जैसे साश्वत मूल्यों को वास्तविक धरातल पर लाना।
2. उच्च शिक्षा के लिये प्रशासनिक एवं विनिमय ढांचा को बदलना।	स्नातक एवं परास्नातक कालेजों का मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग एवं ढांचा गत बदलाव की आवश्यकता है।	व्यवस्थित एवं ठोस कार्यवाही की आवश्यकता
3. शैक्षणिक खर्च को बढ़ाना एवं जी. डी.पी. में शिक्षा मद को और बढ़ाना।	गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता	
4. वित्त के विविध स्रोतों को बढ़ाना		उच्च शिक्षा को विकलांगों एव असमर्थों के दायरे में लाना।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का क्षरण विश्वविद्यालयों की प्राथमिकता का क्षरण निजी शिक्षा संस्थाओं में मूल्यहीनता जैसी ढेरों चुनौतियां हैं। परन्तु हमें इनको दूर करने और सतत् शिक्षा के लिए नवोन्मेषी प्रयास करने होंगे जिसमें ज्ञान के विभागीकरण पर रोक, भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना, साहित्य एवं विज्ञान को समान दर्जा दिया जाये, उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण संस्थानों को विश्वविद्यालय में बदला जाये, शोध संस्थानों एवं शिक्षा संस्थानों के मध्य बेहतर अर्न्तसम्बन्ध स्थापित किये जायें शोधार्थी शिक्षक बने शिक्षक शोधार्थी बनें। उच्च शिक्षा एवं राष्ट्रीय मूल्यों का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाये। और बदलती हुयी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना उच्च शिक्षा को और भी लचीला, समाजोपयोगी बनाना होगा जिससे विकास के पथ पर चल कर भारत पुनः विश्वगुरू की उपाधि धारण कर सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *पाण्डेय, राम शकल (2006), शिक्षा समीक्षा, इलाहाबाद : प्रयाग पुस्तक भवन।*
2. *गुप्ता, एस0 पी0 (2010), आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्यायें; इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।*
3. *रूहेला, सत्यपाल (2010), भारतीय शिक्षा का समाजशास्त्र, जयपुर : राजस्थान, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।*
4. *गुप्ता, एस0पी0 (2016), शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।*
5. *शील, अवनीन्द्र (2007), भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्यायें, कानपुर : साहित्य रत्नालय।*
6. *कुमार, श्रीकृष्ण (2009), प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति, नई दिल्ली, श्री सरस्वती पब्लिकेशन।*

7. *त्यागी, गुरूसरनदास, नन्द विजय कुमार (2009), उदयीमान भारत में शिक्षा, विनोद पुस्तक मन्दिरः आगरा।*
8. *सिंह बी0जी0 (2014), भारत में शिक्षा का अधिकार एवं प्रारम्भिक शिक्षा, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।*
9. *Research Journal of Social and Life Science, Center for Research Studies, Rewa year 01, Volume 1, Dec.-2005, page 661-665.*
10. *Research Journal of Social and Life Science, Center for Research Studies, Rewa year 06, Volume 11, Dec.-2011, page 109-110.*